Sarpanches were entitled to draw the money and spend it for the welfare and other developmental activities in the respective Gram Panchayats. But, unfortunately, the officials of Panchayati Raj Department in the State, without the knowledge of Sarpanches, misused the digital key of bank account of Sarpanches. And they diverted the funds to pay old dues, advance payment of power bills, etc. which is against the norms of the Panchayat Act. Over the last few years, funds allotted by the Union Government are getting diverted and misused. I have also noticed that MGNREGA funds are being diverted and utilized for other schemes. Earlier, mining cess, registration and stamp duty were being given to local bodies which were useful in taking up at least some minimum development work. But in the new Panchayat Act brought in in the year 2018, amendments have been made so that these funds go to the State Government only.

Sir, local bodies are suffering for shortage of funds and are unable to take up minimum development programmes. I request the Union Minister to conduct a comprehensive inquiry into all these deeds and take necessary steps to protect the rights of the local bodies as per the 73rd and 74th Constitution Amendments and ensure that funds are deposited in the concerned village panchayat account so that they can take up minimum necessary development activities for the welfare and betterment of the villages. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Zero Hour matter raised by the hon. Member, Dr. K. Laxman: Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. Sasmit Patra (Odisha) and Dr. Amar Patnaik (Odisha), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra).

**Demand for expansion of Patna Airport and starting air service from Patna to Kathmandu**

**श्री शंभू शरण पटेल** (बिहार): माननीय उपसभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। माननीय उपसभापति महोदय, हमारे नरेन्द्र मोदी जी के कार्यकाल में सभी सेक्टर्स में विकास हुआ है। एयरपोर्ट्स भी 74 से बढ़ कर 148 हो गए हैं, लेकिन पटना का जो एयरपोर्ट है, जिसको हम लोग जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जानते हैं, इसका नाम तो अंतरराष्ट्रीय है, पर वहाँ से एक भी अंतरराष्ट्रीय उड़ान नहीं जाती है। साथ ही, वहाँ का जो रनवे है, वह काफी छोटा है, इसलिए पूरे हिन्दुस्तान में खतरनाक एयरपोर्ट के रूप में उसकी तुलना की जाती है।

अत: मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करूँगा कि पटना का जो जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसके रनवे का विस्तारीकरण किया जाए तथा बाबा काशी

विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए तो वहाँ से फ्लाइट है, इसके साथ ही पटना और बिहारवासियों को बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए भी वहाँ से फ्लाइट की सुविधा मिल जाए, तो अच्छा होगा, ताकि हम पटनावासी, बिहारवासी डायरेक्ट पटना से काठमांडू जाकर बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन कर पाएँ। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से और माननीय नागर विमानन मंत्री जी से यही माँग करना चाहूँगा, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Zero Hour matter raised by the hon. Member, Shri Shambhu Sharan Patel: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur) and Dr. Santanu Sen (West Bengal).

**Demand to complete Indore-Manmad New Rail Line Project**

**डा. सुमेर सिंह सोलंकी** (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, नर्मदे हर! ननीय उपसभापति महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका और सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में इंदौर-मनमाड़ रेल मार्ग की 105 साल पुरानी माँग है, लेकिन वह माँग आज तक पूरी नहीं हुई है। मेरे क्षेत्र के आदिवासी भाइयों और बहनों ने निरंतर रेल का सपना देखा है, लेकिन यह रेल का सपना आज तक अधूरा पड़ा हुआ है। 105 साल पुराने इस रेल मार्ग के बनने से इससे हमारे आदिवासी क्षेत्र के पाँच से अधिक जिले जुड़ेंगे और 13 से अधिक विधान सभा क्षेत्र जुड़ेंगे तथा कई रेलगाड़ियों का सफर 250-600 किलोमीटर तक कम होगा। इसके साथ ही निमाड़ मालवा के ऐसे ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन स्थल, जिनमें महेश्वर, ओंकारेश्वर, महाकाल, मांडू, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, बावनगजा, नागलवाड़ी जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल शामिल हैं, वे भी इस रेल मार्ग से जुडेंगे और आदिवासी-किसान भाइयों और बहनों को भी इससे लाभ होगा। माननीय उपसभापति महोदय, इस रेल मार्ग के पूर्ण होने से आदिवासी क्षेत्र का विकास होगा और मेरे आदिवासी भाइयों और बहनों को कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा करने का अवसर भी प्राप्त होगा, साथ ही सेना के जवानों को भी आवागमन में सुविधा प्राप्त होगी।

माननीय उपसभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह है कि जनजातीय गौरव कॉरिडोर के तहत बजट में 70 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, अगर इसी बजट से इस क्षेत्र में रेल मार्ग का निर्माण किया जाता है, तो मेरे क्षेत्र के आदिवासी भाइयों और बहनों को लाभ होगा और क्षेत्र का विकास भी होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर!

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Zero Hour matter raised by the hon. Member, Dr. Sumer Singh Solanki: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shri Kamakhya Prasad Tasa (Assam), Dr. Sikander Kumar (Himachal Pradesh), Dr. Kalpana Saini (Uttarakhand), Shrimati Darshana Singh